(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस दिशा में सरकार की क्या उपलब्धियां रही है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (ग) विश्व में ऐसी कोई कर प्रणाली नहीं है जो कर अपवंचकों/काला धन उत्पन्न करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा का दावा कर सके।

फिर भी, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ काले धन के उत्पन्न होने को रोकने के लिए निम्नलिखित कानूनी उपाय किए हैः—

(i) आयकर अधिनियम के अध्याय ग के अधीन अचल संपत्ति की पूर्व कृष्याधिकार खरीद।

(ii) धारा 269 ध ध और 269 न के अन्तर्गत ऋणों/जमा राशियों को लेने, भुगतान या अदायगी के तरीके से संबंधित सांविधिक आवश्यकता जिसके द्वारा 20,000/- रु॰ से अधिक के आदाता खाते वाले बैंक ड्राफ्ट से इतर भुगतान/अदायगी के लिये आयकर अधिनियम की धारा 27-झ घ और 27 झ ङ के अन्तर्गत अर्थ दंड लगाया जाता है।

(iii) स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंधों को व्यापक बनाना।

(iv) छोटी आय वालों के लिए धारा 115-ट के अंतर्गत पूर्वानुमानित कर स्कीम आरंभ करना।

(v) कर दरों को कम करना

(vi) कर अपराधियों के लिए अर्थदंड/अभियोजन संबंधी विभिन्न उपबंध।

(vii) तलाशी कर-निर्धारण उपबंधों का सरलीकरण ताकि कम समय में ऐसे कर-निर्धारणों को पूरा किया जा सके और करों की वसूली शीघ्र की जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, आयकर विभाग के सतर्क अधिकारियों द्वारा सुदृढ़ और तुरन्त कार्यवाही करने से हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है और कर वसूलियों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

Sharing of Tax-Revenues between State and Cental Governments

315. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether Government propose to consider any formula to rationalise sharing of different tax-revenues between the State Government and the Central Government; and

(b) if so, the details and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The sharing of tax-revenues between Centre and States from 1995-96 to 1999-2000 shall be in accordance with the recommendations of the Tenth Finance Commission (TFC), as approved by the Government of India. The TFC has recommended that 77.5% of net proceeds of Income-tax, 47.5% of net proceeds of Union Excise Duties and 97.797% of Additional Duties of excise be distributed among States besides Rs. 380 crores annually as grant in lieu of the Railway Passenger Fare Tax.

The TFC has also recommended an alternative scheme of devolue where in Central taxes are to be pooled and a portion of it to devolutive upon States. The Alternative scheme of devloution will require consultation with States followed by a constitutional amendment, if necessary.

Expenditure on Advertisements

316. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the total amount of expenditure incurred by the Ministry on advertisements during the year 1995-96 and till date; and

(b) language-wise details thereof?

THE MINISTER OF INFORMA-TION AND BROADCASTING (SHRI CM. IBRAHIM): (a) The total amount of expenditure committed on release of advertisements to newspapers /periodicals by DAVP during 1995-96 and till date (up to 30.6.96) is Rs. 47, 80, 04, 137/-.

(b) Language-wise details are given in Statement *A* & *B*.